

उत्तरांचल शासन

न्याय विभाग

अधिसूचना

प्रकीर्ण

13 जुलाई, 2006 ई०

संख्या-639/XXXVI(1)2006-8-एक(5)/06-विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39, वर्ष 1987) की धारा 28 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और मुख्य न्यायमूर्ति, उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल के परामर्श से राज्यपाल इस विषय में विद्यमान नियमावली का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तरांचल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –

- (1) यह नियमावली उत्तरांचल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 कही जायेगी।
- (2) यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

2. परिभाषायें –

जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,

- (क) “अधिनियम” का तात्पर्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39 वर्ष 1987) से है,
- (ख) “मुख्य न्यायाधीश” का तात्पर्य उत्तरांचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से है,
- (ग) “अध्यक्ष” का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष अथवा यथास्थिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा यथास्थिति जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा यथास्थिति तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष से है,
- (घ) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है,
- (ङ) “सरकार” का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है,
- (च) “उच्च न्यायालय” का तात्पर्य उत्तरांचल के उच्च न्यायालय से है,
- (छ) “केन्द्रीय प्राधिकरण” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से है,
- (ज) “राज्य प्राधिकरण” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से है,
- (झ) “जिला प्राधिकरण” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से है,
- (ज) “उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से है,
- (ट) “सचिव” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव अथवा, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 8-क के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव अथवा अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से है।
- (ठ) “धारा” का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है,
- (ड) ‘तालुका विधिक सेवा समिति’ का तात्पर्य अधिनियम की धारा 11-क के अधीन गठित तालुक विधिक सेवा समिति से है,

- (ङ) "ताल्लुका" का तात्पर्य जिला अथवा तहसील के उप खण्ड से है,
- (ण) "लोक अदालत" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 19 के अधीन गठित लोक अदालत से है,
- (त) "स्थाई लोक अदालत" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 22-ख के अधीन गठित लोक अदालत से है,
- (थ) इस नियमावली में प्रयुक्त अन्य समस्त शब्दों तथा पदों का, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, अर्थ क्रमशः वही होगा जो अधिनियम में दिया गया है।
3. राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएँ—
- (१) राज्य प्राधिकरण में उसके मुख्य संरक्षक और कार्यकारी अध्यक्ष सहित सत्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे।
 - (२) राज्य प्राधिकरण के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे, अर्थात्—
 - (i) महाधिवक्ता, उत्तरांचल,
 - (ii) प्रमुख सचिव, वित्त,
 - (iii) सचिव, न्याय,
 - (iv) प्रमुख सचिव, राजस्व,
 - (v) अध्यक्ष, उत्तरांचल राज्य विधिक परिषद (बार काउंसिल)
 - (vi) अध्यक्ष, उत्तरांचल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग।
 - (vii) उत्तरांचल राज्य के पुलिस महानिदेशक,
 - (viii) सचिव/निदेशक समाज कल्याण विभाग, उत्तरांचल,
 - (ix) जिला प्राधिकरण के दो अध्यक्ष जिन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाए।
 - (३) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा इस नियम के उपनियम (४) मे विहित अर्हताएँ और अनुभव रखने वाले सदस्यों में से पौँच सदस्य नामित किये जा सकते हैं।
 - (४) राज्य प्राधिकरण का सदस्य नामित किये जाने के लिये वही व्यक्ति अर्ह होगा जो—
 - (क) प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता हो और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, बच्चों, ग्रामीण और शहरी मजदूरों सहित समाज के दुर्बल वर्गों के उत्थान के लिये कार्य कर रहा है, अथवा
 - (ख) विधि अथवा शिक्षा के क्षेत्र का प्रख्यात व्यक्ति, अथवा
 - (ग) प्रतिष्ठित न्यक्ति जो विधिक सेवा योजनाओं के कार्यान्वयन में विशेष रूचि रखता है।
4. राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव की शक्तियां और कृत्य :—
- राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव की अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे—
- (क) समाज के दुर्बल वर्गों सहित अधिनियम के अधीन पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवायें प्रदान करना,
 - (ख) राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विधिक सेवा योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रक्रिया तैयार करना और उनका प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करना,
 - (ग) राज्य सरकार में विभागाध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक गृह व्यवस्था (हाउस कीपिंग), वित्त एवं बजट सम्बन्धी विषयों के सम्बन्ध में शक्तियों का प्रयोग करना,
- आनुषंगिक एवं आकस्मिक व्यय की पूर्ति हेतु रु० 25,000/- की स्थायी अग्रिम धनराशि राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव के व्ययनाधीन रखी जायेगी। राज्य प्राधिकरण के विभिन्न कृत्यों के निर्वहन हेतु समस्त आवश्यक व्यय, जिनमें उसकी बैठकें आयोजित करने के लिये किया गया खर्च भी शामिल है, सदस्य सचिव की पूर्वानुमति से किया जायेगा।
- परन्तु रु० 10,000/- से अधिक के व्यय के लिये कार्यकारी अध्यक्ष का अनुमोदन आवश्यक होगा।

- (घ) राज्य प्राधिकरण की सम्पत्तियों, अभिलेखों और निधियों का प्रबन्धन,
- (ङ) राज्य प्राधिकरण के समुचित रूप से सही—सही लेखे रखना और उनकी नियतकालिक जांच और लेखा परीक्षा,
- (च) राज्य प्राधिकरण का वार्षिक आय—व्यय लेखा तथा तुलन—पत्र तैयार करना,
- (छ) सामाजिक कार्यकर्ताओं और जिला तथा ताल्लुका विधिक सेवा प्राधिकरणों से सम्पर्क बनाए रखना,
- (ज) अद्यतन तथा पूर्ण सांख्यिकीय सूचना रखना, जिसमें समय—समय पर विभिन्न विधायी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति सम्बन्धी सूचना भी शामिल है,
- (झ) वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तावों पर कार्रवाई करना तथा उनके उपयोग प्रमाण—पत्र जारी करना,
- (ञ) राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विभिन्न विधायी सेवा कार्यक्रमों का आयोजन और उनसे सम्बन्धित बैठकों/ संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का संयोजन तथा प्रतिवेदन तैयार करना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना,
- (ट) विधिक सेवा कार्यक्रमों के विषय में जन साधारण की सूचनार्थ दृश्य—शब्द/वृत्तचित्र, प्रचार सामग्री, साहित्य और प्रकाशन, जिसमें नुकड़ नाटक भी शामिल है, तैयार करना,
- (ठ) ग्रामीण विवादों के निराकरण पर अधिक बल देना तथा ग्रामीण विवादों को गांवों में ही निपटाने के लिए प्रभावी और सार्थक विधायी सेवाओं की योजनाएं बनाने के लिए अतिरिक्त उपाय करना,
- (ड) अधिनियम की धारा 4 के खण्ड (ख) के अधीन तैयार की गई योजनाओं के अन्तर्गत सौंपे गए कृत्यों का निष्पादन,
- (ढ) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के कार्यों का समन्वय तथा जिला और तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य पर प्रभावी नियन्त्रण तथा अधिनियम के अधीन तैयार किए गए कार्यक्रमों और योजनाओं को चलाने के लिये उनका मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहायता प्रदान करना,
- (ण) ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन जो राज्य प्राधिकरण के दक्षता पूर्वक कार्य करने के लिए समीचीन हों,
- (त) ऐसी शक्ति का प्रयोग करना तथा ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन जो उसे कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाएं, तथा
- (थ) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन जो समय—समय पर केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा सौंपे जाएं,
- (द) सदस्य सचिव को उन लम्बित मामलों के न्यायिक अभिलेख मांगने का भी अधिकार होगा जिन्हें अधिनियम की धारा 19 और 20 के अधीन गठित लोक अदालत को निर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है। यदि किसी पक्ष द्वारा मुकदमा दायर करने से पहले समझौता करने और लोक अदालत द्वारा अपने मामले के निस्तारण हेतु राज्य प्राधिकरण के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उसे विरोधी पक्षकार को नोटिस तामील करने तथा धारा 19 की उपधारा (5) के प्रस्तार (दो) के अधीन लोक अदालत के अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत किसी विषय से सम्बन्धित अन्य अभिलेख मांगने का भी अधिकारी होगा ताकि मामले को लोक अदालत को निर्दिष्ट किए जाने के लिए आधार तैयार किया जा सके, जिसमें प्रत्येक पक्ष का बयान लेना भी शामिल है।

5. कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति, सेवा शर्त, शक्तियां तथा कृत्य

5.1 कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति तथा सेवा शर्त

राज्य सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश की संस्तुति के अनुसार उत्तरांचल उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। तथापि, ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पदावधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, उसकी अन्य सेवा शर्त ऐसी होंगी जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से समय—समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाएं। लेकिन प्रत्येक अवस्था में वह उसी वेतन और अनुलाभों का हकदार होगा जो उसे कार्यरत न्यायाधीश के रूप में अनुमत्य थे।

- 5.2 (क) कार्यकारी अध्यक्ष राज्य प्राधिकरण का और से अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपेक्षित समस्त निर्णय लेने के लिये सक्षम होगा।
- (ख) वह ऐसे सभी निर्णय लेने के लिये सक्षम होगा जो उत्तरांचल राज्य में किसी न्यायालय में लम्बित मामले के विषय में, जिसमें मुकदमे से पहले की अवस्था वाले सभी मामले भी शामिल हैं, किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से विधिक सहायता, विधिक परामर्श अथवा अन्य विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए अपेक्षित हो।
- (ग) वह उन मामलों के पुनर्विलोकन के लिए सक्षम होगा जिनमें जिला/तहसील प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवाएं प्रदान करने से इन्कार कर दिया गया हो।
- (घ) वह समस्त जिला/तहसील प्राधिकरणों के अध्यक्षों और सचिवों एवम् अन्य न्यायिक अधिकारियों के कार्य और उनके अपने—अपने जनपदों/तहसीलों में अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उनके योगदान की प्रविष्टिया उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भी दर्ज करने तथा माननीय उच्च न्यायालय को सूचित करने के लिए सक्षम होगा। वह ऐसे अधिकारियों के प्रोत्साहन के लिये उन्हें उचित मानदेय जैसे कि वह माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियत करें, को भी देने के लिये सक्षम होंगा।
6. राज्य प्राधिकरण के सदस्यों एवं सदस्य सचिव की पदावधि तथा नियुक्ति की अन्य शर्तें –
- (1) राज्य सरकार द्वारा नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन नामित राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी और ऐसे सदस्य पुनः नामांकित होने के पात्र होंगे।
 - (2) नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन नामित किसी सदस्य को सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से हटाया जा सकेगा, यदि वह—
 - (क) बिना पर्याप्त कारण के राज्य प्राधिकरण को लगातार तीन अथवा दो वर्ष के अन्तराल में हुई पांच बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है, या
 - (ख) निर्णीत दिवालिया है, या
 - (ग) वह किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोषी रहा हो, जिसमें राज्य प्राधिकरण के विचार से नैतिक अक्षमता शामिल है, या
 - (घ) शारीरिक अथवा मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है, या
 - (ड) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका राज्य प्राधिकरण में बना रहना लोक हित के प्रतिकूल है, या
 - (च) राज्य प्राधिकरण की राय में उसका सदस्य बनाए रखना वांछनीय नहीं है।
 - (3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी किसी भी सदस्य को राज्य प्राधिकरण द्वारा उक्त उपनियम के खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट आधार पर हटाया नहीं जाएगा जब तक कि मुख्य न्यायाधीश राज्य सरकार अथवा प्राधिकरण द्वारा उन्हें इस निमित्त निर्दिष्ट किए जाने पर उनके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जांच के पश्चात् संस्तुति करे कि सदस्य को इन कारणों से हटा दिया जाए।
 - (4) सदस्य, अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित कर राज्य प्राधिकरण से त्याग पत्र दे सकता है और ऐसा त्यागपत्र मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने के दिनांक अथवा त्याग पत्र प्रस्तुत करने के 30 दिन समाप्त होने पर, इनमें जो भी पहले हो, प्रभावी होगा।
 - (5) यदि नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन नामित किसी सदस्य की किसी कारण से राज्य प्राधिकरण की सदस्यता समाप्त हो जाती है तो रिक्त उसी रीति से भरी जाएगी जैसे मूल रूप से मनोनयन द्वारा भरी गई थी और इस प्रकार नामित व्यक्ति पूर्ववर्ती सदस्य की शेष पदावधि के लिए सदस्य बना रहेगा।

- (6) सभी सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य हेतु यात्रा करने पर नियमानुसार यात्रा भत्ते एवम् दैनिक भत्ते अंहरित करने के हकदार होंगे।

यदि सदस्य सरकारी कर्मचारी है तो वह यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता उन्हीं दरों से आहरित करने का हकदार होगा जिनके लिए वह उसको लागू सेवा नियमों के अधीन हकदार है और उस विभाग से आहरित करेगा जिसमें वह कार्य कर रहा है, न कि राज्य प्राधिकरण से।

सदस्य सचिव

- (7) राज्य प्राधिकरण का सदस्य सचिव उच्चतर न्यायिक सेवा में संवर्ग के चयन वेतनमान में सेवारत सदस्य, पूर्णकालिक कर्मचारी होगा और उसकी पदावधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकेगा।
- (8) सेवानिवृत्ति आयु, वेतन और भत्ते, लाभ और अधिकारिताएं और अनुशासनिक मामले तथा अन्य सेवा शर्तों जैसे सभी मामलों में सदस्य सचिव उन नियमों द्वारा नियंत्रित होगा जो राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों पर लागू होते हैं और वह राज्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर होगा। तथापि, उसे प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुमन्य होगा।

7. राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी –

- (1) राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या, जिसमें विशेष कार्याधिकारी शामिल हैं, वह होगी जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से समय-समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाए।
- (2) राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या जिसमें विशेष कार्याधिकारी शामिल हैं, जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न किए जाएं, परिशिष्ट 'क' के अनुसार होगी।
- (3) राज्य प्राधिकरण को अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षता पूर्वक निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा पद सृजित किए जाने पर प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की शक्ति होगी। नियुक्तियां राज्य सरकार में ऐसी नियुक्तियों पर लागू नियमों और विनियमों के अनुसार की जाएंगी। तथापि राज्य प्राधिकरण के परामर्श से अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को उच्च न्यायालय/अधीनस्थ न्यायालयों या राज्य सरकार के अन्य विभागों से भी, यथा स्थिति, प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकता है। यदि अधिकारी और अन्य कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर लिए जाते हैं तो ऐसे कर्मचारी नियमानुसार प्रतिनियुक्ति भत्ते के हकदार होंगे।

8. राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्त, वेतन और भत्ते-

- (1) सदस्य सचिव एवम् विशेष कार्याधिकारी से भिन्न राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अवधारित किए जाएं।
- (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट 'क' में दिए गए हैं।
- (3) राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधाओं, भत्तों और लाभों के हकदार होंगे जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं।
- (4) विशेष कार्याधिकारी उत्तरांचल न्यायिक सेवा के ऐसे व्यक्तियों में से मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से पांच वर्ष से अनाधिक के लिए नियुक्त किया जाएंगा, जो सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) के स्तर से निम्न स्तर के नहीं होंगे।
- (5) सेवानिवृत्त आयु, वेतन और भत्ते, लाभ और अधिकारिताओं, अनुशासनिक मामलों और अन्य सेवा शर्तों जैसे सभी मामलों में सदस्य सचिव एव विशेषकार्याधिकारी उन नियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो उस सेवा पर लागू होते हैं जिसके बे सदस्य है। सदस्य सचिव एव विशेषकार्याधिकारी राज्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर होंगे। तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

(6) जब तक विशेषकार्याधिकारी से भिन्न, राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें और निबंधन विहित न किए जाएं, अनुशासनिक मामलों, अवकाष, भविष्य निधि और अन्य विषयों सहित उनकी अहताएं, भर्ती प्रक्रिया तथा अन्य सेवा शर्तें सरकार में समान श्रेणी के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के समान होंगी और उनसे सम्बन्धित नियम आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

9. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

9.1 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की शक्ति एवं कृत्य

राज्य प्राधिकरण के सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात्

- (क) केन्द्रीय और राज्य प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई और अपेक्षित विधिक सहायता, विधिक परामर्श तथा विधिक सेवाओं सम्बन्धी नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं का प्रवर्तन इस समिति का कर्तव्य होगा।
- (ख) यह उच्च न्यायालय के मामलों के लिए अधिनियम अथवा नियमों के अधीन पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता, विधिक परामर्श तथा विधिक सेवाएं प्रदान करेगी।
- (ग) यह उच्च न्यायालय के मामलों के लिए लोक अदालतों का आयोजन एवं संचालन करेगी।
- (घ) यह वार्ता, मध्यस्थता और समझौते द्वारा मामलों को निपटाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- (ड) यह ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जो राज्य प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर प्रत्यायोजित किए जाएं।

9.2 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष

माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष होंगे।

9.3 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव की अहताएं, अनुभव और मानदेय

कोई व्यक्ति तब तक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए अहं न होगा जब तक कि वह उत्तरांचल उच्चतर न्यायिक सेवा से सम्बन्धित उच्च न्यायालय के संयुक्त निबंधक से निम्नवार श्रेणी का अधिकारी न हों और उसे ₹० 1,000/- प्रतिमाह अथवा ऐसी धनराशि का, जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से समिति के अध्यक्ष द्वारा नियत की जाए, मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

9.4 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव की शक्ति एवं कृत्य

समिति का सचिव समिति का प्रमुख अधिकारी होगा, तथा

- (क) समिति की प्रस्तुतियों, लेखों, अभिलेखों तथा निधियों का अभिरक्षक होगा और अध्यक्ष के अधीक्षण एवं निर्देशन में कार्य करेगा।
- (ख) समिति की प्राप्तियों तथा संवितरण लेखों को ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति से सही—सही और समुचित रूप से रखेगा या रखवाएगा जो राज्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- (ग) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ऐसे कृत्यों का निर्वहन और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाएं, तथा
- (घ) ऐसे सभी अन्य कार्य करेगा जो समिति के कृत्यों के दक्षतापूर्वक एवं समुचित निर्वहन और कर्तव्यों के अनुपालन के लिए आवश्यक एवं समीचीन हों।

10. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें वेतन और भत्ते

- (1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या वह होंगी जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित की जाए।

(6) जब तक विशेषकार्याधिकारी से भिन्न, राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्त और निबन्धन विहित न किए जाएं, अनुशासनिक मामलों, अवकाश, भविष्य निधि और अन्य विषयों सहित उनकी अहताएं, भर्ती प्रक्रिया तथा अन्य सेवा शर्त सरकार में समान श्रेणी के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के समान होंगी और उनसे सम्बन्धित नियम आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

9. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

9.1 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की शक्ति एवं कृत्य

राज्य प्राधिकरण के सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात्

- (क) केन्द्रीय और राज्य प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई और अपेक्षित विधिक सहायता, विधिक परामर्श तथा विधिक सेवाओं सम्बन्धी नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं का प्रवर्तन इस समिति का कर्तव्य होगा।
- (ख) यह उच्च न्यायालय के मामलों के लिए अधिनियम अथवा नियमों के अधीन पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता, विधिक परामर्श तथा विधिक सेवाएं प्रदान करेगी।
- (ग) यह उच्च न्यायालय के मामलों के लिए लोक अदालतों का आयोजन एवं संचालन करेगी।
- (घ) यह वार्ता, मध्यस्थता और समझौते द्वारा मामलों को निपटाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- (ङ) यह ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जो राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किए जाएं।

9.2 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष

माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष होंगे।

9.3 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव की अहताएं, अनुभव और मानदेय

कोई व्यक्ति तब तक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए अहं न होगा जब तक कि वह उत्तरांचल उच्चतर न्यायिक सेवा से सम्बन्धित उच्च न्यायालय के संयुक्त निबंधक से निम्नवार श्रेणी का अधिकारी न हों और उसे ₹० 1,000/- प्रतिमाह अथवा ऐसी धनराशि का, जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से समिति के अध्यक्ष द्वारा नियत की जाए, मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

9.4 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव की शक्ति एवं कृत्य

समिति का सचिव समिति का प्रमुख अधिकारी होगा, तथा

- (क) समिति की प्रसिद्धियों, लेखों, अभिलेखों तथा निधियों का अभिरक्षक होगा और अध्यक्ष के अधीक्षण एवं निर्देशन में कार्य करेगा।
- (ख) समिति की प्राप्तियों तथा संवितरण लेखों को ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति से सही-सही और समुचित रूप से रखेगा या रखवाएगा जो राज्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- (ग) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ऐसे कृत्यों का निर्वहन और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाएं, तथा
- (घ) ऐसे सभी अन्य कार्य करेगा जो समिति के कृत्यों के दक्षतापूर्वक एवं समुचित निर्वहन और कर्तव्यों के अनुपालन के लिए आवश्यक एवं समीचीन हों।

10. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और उनकी सेवा शर्त वेतन और भत्ते

- (1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या वह होंगी जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएं।

- (2) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या, जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश पारित न किए जाएं, परिशिष्ट 'ख' में दी गयी है।
- (3) इस नियमावली के प्रारम्भ होने से एकदम पहले उच्च न्यायालय विधिक सहायता एवं परामर्श समिति में कार्यरत सचिव से भिन्न समस्त अधिकारी और कर्मचारी इस नियमावली के प्रारम्भ होने पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी और कर्मचारी होंगे।
- (4) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसा वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किए जाएं।
- (5) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट 'ख' के अनुसार होंगे।
- (6) जब तक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्ते और निबन्धन विहित न किए जाएं, अनुशासनात्मक मामलों, अवकाश, भविष्य निधि और अन्य विषय सहित उनकी अर्हताएं, भर्ती प्रक्रिया तथा अन्य सेवा शर्तें समान श्रेणी के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के समान होंगी और उनसे सम्बन्धित नियम आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
- (7) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधाओं, भत्तों और लाभों के हकदार होंगे, जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं।

11. जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की संख्या, अवधि, अनुभव एवं अर्हताएँ

- (1) जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होंगे। इस क्षेत्र में जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें मानदेय के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान किया जा सकेगा जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा नियत की जाए तथा उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में उत्तम/उत्कृष्ट प्रविष्टि भी की जाए।
- (2) जिला प्राधिकरण में उप नियम (3) के अधीन नामित सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे:-
 - (क) जिला अधिकारी
 - (ख) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस अधीक्षक, यथास्थिति,
 - (ग) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 - (घ) जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल)
 - (ड) जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध),
 - (च) जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व),
 - (छ) जिला बार ऐसोसिएशन के अध्यक्ष,
- (3) सरकार, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उपनियम (4) में विर्तिदिष्ट अनुभव एवं अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों में से जिला प्राधिकरण के छ: अन्य सदस्यों को मनोनीत कर सकती है, जिनकी अवधि दो वर्ष होगी और वे पुनःनामांकित होने के पात्र होंगे।
- (4) जिला प्राधिकरण का सदस्य नामित किये जाने के लिए वही व्यक्ति अर्ह होगा जो :-
 - (क) प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता हो और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, बच्चों, ग्रामीण और शहरी मजदूरों सहित समाज के दुर्बल वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है।
 - (ख) विधि के क्षेत्र का प्रख्यात व्यक्ति, या
 - (ग) प्रतिष्ठित व्यक्ति जो विधिक सेवाओं के कार्यान्वयन में विशेष रूचि रखता हो।

12. जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या

- (1) सिविल जज, (सीनियर डिवीजन) अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, यथास्थिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सचिव होंगे और मानदेय के रूप में 500 / रु० प्रतिमाह अथवा ऐसी धनराशि का भुगतान किया जाएगा, जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य प्राधिकरण द्वारा नियत की जाए।
- (2) जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य सदस्यों की संख्या वह होगी जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित की जाए।
- (3) इस नियमावली के प्रारम्भ होने से एकदम पहले जिला विधिक सहायता एवं परामर्श समिति में कार्यरत समस्त अधिकारी और अन्य कर्मचारी इस नियमावली के प्रारम्भ होने पर जिला प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी होंगे।

13. जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतन और भत्ते

- (1) जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किए जाएं।
- (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट 'ग' के अनुसार होंगे।
- (3) जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधाओं भत्तों और लाभों के हकदार होंगे जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं।
- (4) जब तक जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें और निबन्धन विहित न किए जाए, अनुशासनिक मामलों, अवकाश, भविष्य निधि और अन्य विषयों सहित उनकी अर्हताएं, भर्ती प्रक्रिया तथा अन्य सेवा शर्तें समान श्रेणी के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के समान होंगी और उनसे सम्बन्धित नियम आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

14. तहसील विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अवधि, अनुभव और अर्हताएं

- (1) तहसील विधिक सेवा समिति में पांच से अधिक सदस्य नहीं होंगे।
- (2) तहसील विधिक सेवा समिति में उपनियम (3) के अधीन नामित सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे:—
 - (क) यदि किसी स्तर का ज्येष्ठतम न्यायिक अधिकारी तहसील या उपखण्ड में तैनात है तो वह तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा और ऐसे कनिष्ठतम अधिकारी सचिव के रूप में कार्य करेगा। यदि किसी तहसील में केवल एक न्यायिक अधिकारी कार्यरत हो तो तहसीलदार सचिव के रूप में कार्य करेगा और सचिव को रु० 300/- प्रतिमाह की दर से अथवा ऐसी धनराशि जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जिला प्राधिकरण द्वारा नियत की जाए, का मानदेय के रूप में भुगतान किया जायेगा।
 - (ख) यदि उपखण्ड अधिकारी तहसील या उपखण्ड में तैनात है, या उसकी अनुपस्थिति में तहसील का तहसीलदार, यदि न्यायिक अधिकारी उपखण्ड में तैनात नहीं है, यथास्थिति, तहसील समिति के अध्यक्ष/सचिव के रूप में कार्य करेगा और उसे मानदेय की ऐसी राशि का भुगतान किया जाएगा जो किसी न्यायिक अधिकारी को अनुमन्य है।
 - (ग) तहसील की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत तैनात ज्येष्ठतम राजपत्रित पुलिस अधिकारी।
- (3) सरकार, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अनुभव एवं अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों में से तहसील विधिक सेवा समिति के अन्य तीन सदस्य मनोनीत कर सकती है जिनकी अवधि दो वर्ष होगी और वे पुनःनामांकित होने के पात्र होंगे।
- (4) तहसील विधिक सेवा समिति का सदस्य नामित किए जाने के लिए वही व्यक्ति अर्ह होगा जो,

- (क) सम्बन्धित तहसील की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत रहने वाला स्थायी निवासी प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता हो और जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, बच्चों, ग्रामीण और शहरी मजदूरों सहित समाज के दुर्बल वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है।
- (ख) विधि क्षेत्र का प्रख्यात व्यक्ति, अथवा
- (ग) प्रतिष्ठित व्यक्ति जो विधिक सेवा योजनाओं में विशेष रूप से रखता हो।

15. तहसील विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या

- (1) तहसील विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या वह होगी जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।
- (2) तहसील विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किए जाएं।
- (3) तहसील विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधाओं, भत्तों और लाभों के हकदार होंगे जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किए जाएं।
- (4) जब तक तहसील विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें और निबन्धक विहित न किए जाएं, अनुशासनिक मामलों, अवकश, भविष्य निधि और अन्य विषयों सहित उनकी अर्हताएं, भर्ती प्रक्रिया तथा अन्य सेवा शर्तें समान श्रेणी के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के समान होंगी और उनसे सम्बन्धित नियम आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

16. निःशुल्क विधिक सेवा के लिए हक व पात्रता

प्रत्येक व्यक्ति, जिनसे कोई मामला फाइल करना है या फाइल कर दिया गया है या किसी मामले में बचाव करना है, इस अधिनियम के अधीन, राज्य प्राधिकरण या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण या ताल्लुक प्राधिकरण से जैसे भी केस हो, निःशुल्क विधिक सेवा का हकदार होंगा, यदि ऐसे व्यक्ति

- (1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी नागरिक,
- (2) संविधान के अनुच्छेद-23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
- (3) सभी महिलायें एवं बच्चे,
- (4) सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
- (5) बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़ एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसी दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
- (6) औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
- (7) जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरुद्ध सभी व्यक्ति,
- (8) ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 50,000/- रुपये से कम हो,
- (9) भूतपूर्व सैनिक,

नोट:-क्रम संख्या-1 से 7 व 9 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

17. लोक अदालतें, समझौता केन्द्र और विधिक साक्षरता शिविर

- 17.1 धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएं लोक अदालत की खण्डपीठ में शामिल किए जाने के लिए वही व्यक्ति अर्ह होगा जो:-

- (क) प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता हो और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, बच्चों, ग्रामीण और शहरी मजदूरों सहित समाज के दुर्बल वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा हो, अथवा।
- (ख) ख्याति प्राप्त वकील हो, अथवा।
- (ग) प्रतिष्ठित व्यक्ति जो विधिक सेवा योजनाओं और कार्यक्रमों में विशेष रूचि रखता है।

17.2 उच्च न्यायालय में लोक अदालत, साक्षरता शिविर और समझौता केन्द्र

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जब भी आवश्यक हो लोक अदालतों की खण्डपीठ गठित करेगा। प्रत्येक खण्डपीठ में निम्नलिखित में से कोई दो या तीन सदस्य होंगे, अर्थात् (एक) उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कोई अन्य सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी जो जिला न्यायाधीश के पद से निम्न पद पर न हो,

- (दो) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सदस्य सचिव/सचिव,
- (तीन) विधि व्यवसाय का सदस्य जिसे 10 वर्ष से कम का अनुभव न हो।
- (चार) प्रतिष्ठित स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के दुर्बल वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है।

17.3 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष अधिनियम के अधीन निर्धारित मानदण्ड पूरा करने वाले व्यक्ति को विधिक सेवाएं प्रदान करने तथा विनिश्चय हेतु उच्च न्यायालय का निर्दिष्ट किए जाने के लिए मामलों की जांच करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय में एक समझौता केन्द्र का भी गठन करेगा। सचिव समझौता केन्द्र का प्रधान, होगा और उसमें निम्नलिखित दो सदस्य होंगे, अर्थात्,

- (एक) विधि व्यवसाय का सदस्य जिसे कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो,
- (दो) प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के दुर्बल वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा हो।

17.4 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य में ऐसे स्थानों पर विधिक साक्षरता शिविरों का भी आयोजन कर सकता है जो अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उचित एवं आवश्यक समझे जाएं।

17.5 लोक अदालत के आयोजन के लिए किया गया व्यय 10,000 / रु० या ऐसी अन्य राशि से अधिक नहीं होगा जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर नियत किया जाए। साक्षरता शिविर के आयोजन के लिए किया गया व्यय 15,000 / रु० या ऐसी अन्य राशि से अधिक नहीं होगा जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर नियत किया जाए।

17.6 जिला प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत, समझौता केन्द्र और साक्षरता केन्द्रों का आयोजन-

पारम्पारिक लोक अदालतों के अतिरिक्त जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा अपने जिले में जिला मुख्यालय अथवा किसी तहसील में महीने में कम से कम एक लोक अदालत और एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाएगा। तथापि ऐसी लोक अदालत को निर्दिष्ट मामलों की संख्या के अनुसार महीने के किसी शनिवार या रविवार को ऐसी लोक अदालत का आयोजन किया जा सकता है। एक बार मामला ऐसी अदालत को निर्दिष्ट किए जाने के बाद सौहार्दपूर्ण समाधान होने तक अथवा ऐसे समय तक जब यह अनुभव किया जाए कि कोई सौहार्दपूर्ण समाधान संभव नहीं है और मामले को विधि के अनुसार निर्णय के लिए सम्बन्धित न्यायालय को वापस भेजना पड़ेगा, मामला अगली लोक अदालत तक स्थगित किया जा सकता है। ऐसी लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी को मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य प्राधिकरण द्वारा नियत धनराशि का मानदेय के रूप में भुगतान किया जा सकता है, तथापि अधिकारियों को लोक अदालत और साक्षरता शिविरों के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में समुचित प्रविष्टियों जैसे अन्य प्रोत्साहन द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। ऐसी लोक अदालतों को निर्दिष्ट मामलों की संख्या के आधार पर पृथक-पृथक जिलों/तहसीलों में आवश्यकतानुसार जिला प्राधिकरण द्वारा लोक अदालतों की अधिक खण्डपीठों का गठन किया जा सकता है प्रत्येक खण्डपीठ में

निम्नलिखित में से एक या दो सदस्य होंगे, अर्थात्

(क) जिला मुख्यालय अथवा तहसील में कार्यरत न्यायिक अधिकारी,

(ख) विधि व्यवसाय का सदस्य जिसे कम से कम 07 वर्ष का अनुभव हो,

(ग) प्रतिष्ठित (स्थानीय) सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के दुर्बल वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है।

टिप्पणी :- यदि उपर्युक्त 'ख' या 'ग' उल्लिखित व्यक्तियों में से उपयुक्त सदस्य आसानी से उपलब्ध न हों तो केवल न्यायिक अधिकारी द्वारा ही लोक अदालत का गठन किया जा सकता है।

17.7 जिला मुख्यालय या तहसील मुख्यालय में लोक अदालत या साक्षाता शिविर के आयोजन पर किए जाने वाले व्यय की सीमा वही होगी जो नियम 17.5 के अधीन विहित है।

17.8 राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा अधिनियम के अधीन पात्र व्यक्तियों को सक्रिय विधिक परामर्श और सहायता प्रदान करने तथा लोक अदालत को निर्दिष्ट किए जाने के लिए मामलों की जांच के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय में समझौता/केन्द्र/केन्द्रों का गठन किया जाएगा। जिला मुख्यालय में ऐसे समझौता केन्द्र का प्रधान जिला प्राधिकरण का और तहसील मुख्यालय में तहसील समिति का अध्यक्ष होगा। समिति में निम्नलिखित में से एक या दो सदस्य होंगे।

(एक) विधि व्यवसाय का सदस्य जिसे कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो,

(दो) प्रतिष्ठित स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के दुर्बल वर्गों के उत्थान का कार्य कर रहा है।

यदि जिले/तहसील में एक से अधिक केन्द्रों का सृजन किया गया है तो उनकी व्यवस्था ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जिसे कम से कम 10 वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव हो।

17.9 राज्य स्तरीय समझौता केन्द्र

कार्यकारी अध्यक्ष स्वविवेकानुसार विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अधिनियम के अधीन सक्रिय विधिक सहायता के पात्र व्यक्तियों को ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर एक या एक से अधिक समझौता केन्द्रों का गठन करेंगे, ताकि अधिनियम के उद्देश्यों को पूर्णतया प्राप्त किया जा सके। यदि एक से अधिक ऐसे केन्द्रों का गठन किया जाता है तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव या कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति तहसील स्तर के ऐसे केन्द्रों को प्रधान होगा। प्रत्येक ऐसे केन्द्रों में कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा सहायतार्थ निम्नलिखित एक या दो सदस्यों को भी मनोनीत किया जा सकेगा, अर्थात् :

(एक) विधि व्यवसाय का सदस्य जिसे कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो,

(दो) प्रतिष्ठित स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के दुर्बल वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा हो।

यदि एक से अधिक ऐसे केन्द्र सृजित किए जाते हैं तो विधि व्यवसाय के ऐसे सदस्य को ऐसे केन्द्र में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है जिसे कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।

17.10 समझौता केन्द्र/केन्द्रों में प्रतिनियुक्त व्यक्ति को मानदेय का भुगतान

केन्द्रीय प्राधिकरण अथवा राज्य सरकार से निधियां उपलब्ध होने पर कार्यकारी अध्यक्ष, यथास्थिति, केन्द्रीय अथवा राज्य प्राधिकरण के परामर्श से उच्च न्यायालय, राज्य या जिला/तहसील स्तर पर यथास्थिति, गठित ऐसे समझौता केन्द्र में कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को मानदेय के भुगतान हेतु उतनी राशि नियत करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जो वह उचित और आवश्यक समझें।

17.11 सूचीबद्ध (पैनल) वकीलों की फीस का भुगतान

राज्य प्राधिकरण मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य अथवा जिला प्राधिकरण के विनिश्चय के अनुसार निर्धनों को विधिक परामर्श और सहायता प्रदान करने वाले सूचीबद्ध वकीलों को दी जाने वाली फीस की मात्रा नियत करेंगे। राज्य

प्राधिकरण द्वारा अपनायी गई तत्समय प्रवृत्त ऐसी भुगतान दरें परिशिष्ट 'घ' में दी गई है। तथापि ऐसे भुगतान में राज्य प्राधिकरण द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से वृद्धि की जा सकती है जैसा उचित और आवश्यक समझी जाए।

18. स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष की नियुक्ति, सेवाशर्त, वेतन और भत्ते

- (क) ऐसा व्यक्ति, जो जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश है या रहा है या जिसने जिला न्यायाधीश के समतुल्य न्यायिक पद धारण किया हो, स्थाई लोक अदालत का अध्यक्ष होगा।
- (ख) राज्य प्राधिकरण की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा उसकी नियुक्ति की जाएगी जिसकी पदावधि अधिक से अधिक पांच वर्ष अथवा 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें जो भी पहले हो, होगी।
- (ग) यदि कोई सेवारत न्यायिक अधिकारी अध्यक्ष, नियुक्त किया जाता है तो वह उस वेतन और भत्तों तथा समस्त अन्य अनुलाभों का हकदार होगा जो उसे सेवारत अधिकारी के रूप में अनुमन्य थे, लेकिन जब कोई सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो वह उस वेतन और भत्तों तथा समस्त अन्य अनुलाभों का हकदार होगा जो उसके द्वारा सेवारत न्यायिक अधिकारी के रूप में अन्तिम बार आहरित किए गए जिसमें से ऐसे न्यायिक अधिकारी की सेवानिवृत्त पर नियत पेशन राशि घटा दी जाएगी।

19. स्थाई लोक अदालत के अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति, बैठक फीस अन्य भत्ते

- (क) राज्य प्राधिकरण की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक सुविधा सेवा के पर्याप्त अनुभवी दो अन्य सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा।
- (ख) उनकी पदावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे राज्य प्राधिकरण की संस्तुति पर सरकार द्वारा दो वर्ष की अवधि तक आगे बढ़ाया जा सकता है।
- (ग) ऐसे सदस्य 500 / रु० प्रति बैठक की दर से बैठक फीस के हकदार होंगे।
- (घ) अध्यक्ष और अन्य व्यक्ति सरकारी दौरे पर ऐसे यात्रा और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को अनुमन्य हैं।
- (ड) स्थाई लोक अदालत की बैठक में उपस्थित रहने के लिए ऐसा अन्य व्यक्ति 2500 / रु० प्रतिमाह यात्रा भत्ते का हकदार होगा।
- (च) नियुक्ति से पहले अध्यक्ष और अन्य व्यक्ति को वचन देना होगा कि उसका ऐसा कोई वित्तीय अथवा अन्य हितलाभ नहीं है और न होगा जिससे अध्यक्ष अथवा अन्य व्यक्ति के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।
- (छ) पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष अथवा अन्य व्यक्ति
 - (क) यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण को सम्बोधित लिखित त्याग पत्र द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकते हैं।
 - (ख) उन्हें नियम 20 के उपबन्धों के अनुसार पद से हटाया जा सकता है।
- (ज) यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी अथवा किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों के निवर्हन में असमर्थ हो तो उनके द्वारा अपने कृत्यों का प्रभार पुनः ग्रहण करने के दिनांक तक तत्समय पदधारण करने वाला ज्येष्ठतम (नियुक्ति के क्रम में) व्यक्ति अध्यक्ष के कृत्यों का निवर्हन करेगा।
- (झ) अध्यक्ष अथवा कोई अन्य व्यक्ति पद त्यागने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक ऐसे संगठन में नियुक्त नहीं होगा अथवा उसके प्रबन्धन या प्रशासन से सम्बन्धित नहीं होगा जिस पर उसकी पदावधि में अधिनियम के अधीन कार्यवाही चल रही है।

20. त्याग पत्र और पद से हटाया जाना

राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा, यथास्थिति, स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति को पद से हटाया जा सकेगा यदि वह :-

(क) निर्णीत दिवालिया हो, या

(ख) ऐसे अपराध का सिद्ध दोषी है जिसमें प्राधिकरण के विचार से नैतिक अधमता शामित है, या

(ग) अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है, या

(घ) ऐसा वित्तीय अथवा अन्य हितलाभ प्राप्त कर लिया है जिसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, या

(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल होगा।

परन्तु, अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य को नियम 21 में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के सिवाय खण्ड (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट कारणों के आधार पर पद से हटाया नहीं जाएगा।

21. जांच प्रक्रिया

- (1) यदि, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण, की राय में किसी आरोप की नियम 5 के खण्ड (घ) और (ङ) के अधीन जांच की जानी अपेक्षित है तो वह अभियुक्त के विरुद्ध जांच कर सकेगा और आरोप का सारांश तैयार करेगा या करवायेगा जिसमें संगत तथ्यों का विवरण और दस्तावेजों तथा साक्ष्यों की सूची होगी।
- (2) राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण, यथास्थिति, अभियुक्त को आरोप और दस्तावेजों तथा साक्ष्यों की सूची की एक प्रति देगा या दिलवायेगा तथा उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसे समय के अन्दर, जिसकी अनुमति दी जाए, अपने बचाव में लिखित उत्तर अथवा विवरण प्रस्तुत करें।
- (3) यदि अभियुक्त द्वारा आरोप स्वीकार कर लिए जाते हैं तो यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा अभियुक्त को पद से हटा दिया जाएगा और कारण अभिलिखित किए जाएंगे।
- (4) यदि अभियुक्त आरोपों को स्वीकार करने से इन्कार करता है तो राज्य प्राधिकरण अथवा जनपद प्राधिकरण द्वारा, यथास्थिति, आरोपों की सत्यता की जांच करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है और उसके द्वारा राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण, यथास्थिति, की ओर से जांच अधिकारी के समक्ष मामला प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी भी नियुक्त किया जा सकेगा।
- (5) जांच अधिकारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को अपना मामला ऐसे समय के अन्दर प्रस्तुत करने का अवसर देगा जिसकी उसके (जांच अधिकारी) द्वारा समय—समय पर अनुमति दी जाए। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् जांच अधिकारी अभियुक्त को ऐसे समय के अन्दर जिसकी अनुमति दी जाए, आरोपों के बचाव में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देगा।
- (6) जांच अधिकारी का गवाहों को बुलाने और उनके बयान दर्ज करने या शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने या दस्तावेज या अन्य संगत अभिलेख, जो जांच के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने की मांग करने की शक्ति होगी।
- (7) जांच अधिकारी छ: महीने की अवधि या ऐसे समय के अन्दर जो, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया जाए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (8) यदि राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण, यथास्थिति, का समाधान हो जाता है कि आरोप जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर सिद्ध हो गए हैं तो वह अपचारी अध्यक्ष अथवा सदस्य को, जैसी भी स्थिति हो, उनके पद से हटा देगा।

22. बैठकों का स्थान

- (1) स्थाई लोक अदालत की बैठक उस स्थान पर होगी जो राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण, यथास्थिति, द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (2) स्थाई लोक अदालत के कार्य दिवस और कार्य समय वही होगा जो राज्य सरकार का होगा।
- (3) स्थाई लोक अदालत की बैठक जब कभी भी आवश्यक हो, अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी।

23. स्थाई लोक अदालत के कर्मचारी

राज्य सरकार द्वारा स्थाई लोक अदालत को अपने दैनिक कार्यों और इस अधिनियम और इन नियमों द्वारा प्रदान किए गए ऐसे अन्य कृत्यों के निष्पादन में सहायता के लिए जो उसे अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए हैं, उतने कर्मचारी प्रदान किए जाएंगे जो आवश्यक हों। ऐसे कर्मचारियों का वेतन, राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा।

24. निरसन एवं व्यावृत्ति

- (1) उत्तरांचल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली—2006 के प्रवृत्त होने पर, उत्तरांचल राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली—1996 का प्रभाव निरसित हो जायेगा।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपरोक्त नियमावली के प्रभावी होने से पहले उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली—1996 के अन्तर्गत किये गये समस्त कार्य एवम् कार्यवाही सुरक्षित रहेगी।

परिशिष्ट “क”

[नियम 7 (2) और 8 (2) देखिये]

क्र.स.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	सदस्य सचिव	1	उत्तरांचल उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को अनुमन्य सेलेक्शन वेतनमान
2.	विशेष कार्य अधिकारी	1	सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को अनुमन्य वेतनमान
3.	निजी सचिव	1	रु. 6500—10200रु.
4.	निजी सहायक	2	5500—9000रु.
5.	आशुलिपिक	2	4000—6000रु.
6.	प्रशासनिक अधिकारी	1	5500—9000रु.
7.	प्रवर वर्ग सहायक	2	4500—7000रु.
8.	लेखा लिपिक	1	4000—6000रु.
9.	टंकक	2	3050—4590रु.
10.	कनिष्ठ लिपिक	2	3050—4590रु.
11.	पुस्तकालय लिपिक	1	3050—4590रु.
12.	अर्दली / चपरासी	6	2550—3200रु.
13.	दतरी / मशीन आपरेटर	1	2610—3550रु.
14.	ड्राइवर	3	3050—4590रु.
15.	स्वीपर सह फर्माश	1	2,000 रुपये प्रति माह (फिकस्ड)

परिशिष्ट “ख”

{नियम 10(2) और 10(5) देखिये}

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	लिपिक	2	3050—4590 रु.
2.	अर्दली रु.	2	2550—3200 रु.

परिशिष्ट “ग”

{नियम 12(2) और 13(2) देखिये}

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	लिपिक	13	3050—4590 रु.
2.	चपरासी	13	2550—3200 रु.

परिशिष्ट “घ”

{नियम 17(11) देखिये}

पब्लिक सर्विस ट्रिब्युनल

1. ट्रिब्युनल के समक्ष कार्यवाही करने के लिए	—	प्रथम तीन दिन के लिये रु० 150/- तत्पश्चात् रु० 100/- प्रतिदिव अधिकतम रु० 1500/-
2. विधिक परामर्श	—	रु० 250/- प्रति वाद।
3. ड्राफिटंग एण्ड प्लीडिंग जिसमें रिज्वाइन्डर व शपथ—पत्र शामिल हैं	—	रु० 500/- मय परामर्श।

श्रम न्यायालयों के लिए

1. ड्राफिटंग/प्लीडिंग जिसमें विधिक सलाह शामिल है।	—	रु० 250/-
---	---	-----------

मजिस्ट्रेट न्यायालय में**जमानत प्रार्थना—पत्र :**

1. जमानत प्रार्थना—पत्र (जमानती)	—	रु० 100/- प्रति प्रार्थना—पत्र।
2. जमानत प्रार्थना—पत्र (बिना जमानती)	—	रु० 300/- प्रति प्रार्थना—पत्र।
3. प्रकीर्ण प्रार्थना—पत्र	—	रु० 250/- प्रति प्रार्थना—पत्र।
4. पंचायत के विरुद्ध अपील/रिवीजन	—	रु० 300/- प्रति अपील/रिवीजन।
5. सिविल वाद में विधिक सलाह	—	रु० 250/- प्रति वाद।
6. फौजदारी वाद में विधिक सलाह	—	रु० 250/- प्रति वाद।

राजस्व वादों में जिनमें चकबन्दी वाद भी शामिल है।

1. उच्च न्यायालय	—	रु० 2500/-
2. बोर्ड ऑफ रेवेन्यु	—	रु० 1500/- प्रति वाद।
3. कमिशनर/एडिशनल कमिशनर/ डी.डी.सी./ज्वाइन्ट डाइरेक्टर	—	रु० 1000/- प्रति वाद।
4. सहायक कलेक्टर/एस.ओ.सी/ अतिरिक्त कलेक्टर	—	रु० 750/- प्रति वाद।
5. तहसीलदार/सी.ओ./ए.सी.ओ	—	रु० 500/- प्रति वाद।
6. राजस्व मामलों में विधिक सलाह	—	रु० 300/- प्रति वाद।

सत्र न्यायालय में

1. सत्र विचारण	—	रु० 200/- प्रतिदिन तीन दिन के लिए और अधिकतम पूर्ण केस के लिए रु० 2000/-
2. प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध क्रिमिनल अपील	—	रु० 1000/- प्रति अपील।
3. द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध क्रिमिनल अपील	—	रु० 500/- प्रति अपील।
4. क्रिमिनल रिवीजन	—	रु० 1000/- प्रति रिवीजन।
5. जमानत प्रार्थना-पत्र	—	रु० 500/- प्रति प्रार्थना-पत्र।

**न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज वरिष्ठ प्रभाग/
सिविल जज कनिष्ठ प्रभाग**

1. मूल वाद	—	रु० 1000/प्रति वाद।
2. वारण्ट केस विचारण	—	रु० 1000/- प्रति वाद।
3. समन केसेज	—	रु० 500/- प्रति वाद।
4. सत्र न्यायालय में कमिट्टि जिसमें रिमाण्ड कार्यवाही शामिल है।	—	रु० 250/- प्रति वाद।

जिला एवं सत्र न्यायालय/अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/परिवार न्यायालय

1. दिवानी वाद में परामर्श	—	रु० 300/- प्रति वाद।
2. फौजदारी वाद में परामर्श	—	रु० 300/- प्रति वाद।
3. ड्राफिटंग ऑफ सिविल प्लीडिंग	—	रु० 500/- प्रति वाद।
4. ड्राफिटंग ऑफ क्रिमिनल कम्प्लेन्ट	—	रु० 500/- प्रति वाद।
5. वैवाहिक/रेन्ट केसेज	—	रु० 1500/- प्रति वाद।
6. सिविल अपील	—	रु० 1500/- प्रति वाद।
7. एकपक्षीय/वाद वापस लेने/संघि के अनुसार निर्णित	—	रु० 500/- प्रति वाद।

८. सिविल रिवीजन	—	रु० ७५०/- प्रति रिवीजन।
९. क्रिमिनल अपील	—	रु० ७५०/- प्रति अपील।
१०. दिवालिया / उत्तराधिकारी प्रार्थना पत्र	—	रु० ७५०/- प्रति प्रार्थना-पत्र।

मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद

१. मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद (घायल होने पर)	—	रु० १०००/- प्रति वाद।
२. मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद (मृत्यु होने पर)	—	रु० १०००/- प्रति वाद।

मा० उच्च न्यायालय

१. रिट पिटीशन	—	अधिकतम रु० ४०००/- प्रति केस हाई कोर्ट रत्तर पर केस के निस्तारण के बाद अन्य आनुशांगिक व्यय को छोड़कर।
२. हेबियस कारपस पिटीशन	—	रु० २५००/- प्रति पिटीशन।
३. प्रथम सिविल अपील	—	रु० ३०००/- प्रति अपील।
४. सिविल रिवीजन	—	रु० ७५०/- प्रति रिवीजन।
५. क्रिमिनल अपील	—	रु० २०००/- प्रति अपील।
६. क्रिमिनल रिवीजन	—	रु० ७५०/- प्रति रिवीजन।
७. जमानत प्रार्थना-पत्र	—	रु० १५००/- प्रति जमानत प्रार्थना पत्र।
८. सिविल वाद में लिखित सलाह	—	रु० ७५०/- प्रति परामर्श।
९. शपथ-पत्र व प्रकीर्ण प्रार्थना-पत्र तैयार करने के लिए	—	रु० ७५०/- प्रति झापट।

प्रकीर्ण

१. निष्पादन वाद	—	रु० १०००/- प्रति वाद।
२. जेल मीटिंग	—	रु० २५०/-

आज्ञा से
श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव, न्याय

No. 639/XXXVI (1) 2006-8-Ek (5) 2006 - In exercise of the powers conferred by section 28 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act No. 39 of 1987) and in consultation with the Chief Justice, the Governor is pleased to make the following rules:

**NOTIFICATION
(Miscellaneous)
July 13, 2006**

THE UTTARANCHAL STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY RULES 2006

1. Short title and commencement.

- (1) These rules may be called the Uttaranchal State Legal Services Authority Rules, 2006.
- (2) These shall come into force on such date as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions -

In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act No. 39 of 1987);
- (b) "Chief Justice" means the Chief Justice of the High Court of Uttaranchal;
- (c) "Chairman" means the Executive Chairman of the State Authority, or, as the case may be, the Chairman of the High Court Legal Services Committee, or, as the case may be, the Chairman of the District Authority, or, as the case may be, the Chairman of the Taluk Legal Services Committee;
- (d) "Governor" means the Governor of Uttaranchal;
- (e) "Government" means the Government of Uttaranchal;
- (f) "High Court" means the High Court of Uttaranchal;
- (g) "Central Authority" means the National Legal Services Authority constituted Under Section 3 of the Act;
- (h) "State Authority" means the State Legal Services Authority constituted Under Section 6 of the Act;
- (i) "District Authority" means the District Legal Services Authority constituted Under Section 9 of the Act;
- (j) "High Court Legal Services Committee" means the High Court Legal Services Committee constituted Under Section 8-A of the Act;
- (k) "Secretary" means the Member-Secretary of the State Legal Services Authority constituted Under Section 6 of the Act, or, as the case may be, the Secretary of the High Court Legal Services Committee constituted Under Section 8-A of the Act, or, as the case may be, the Secretary of the District Legal Services Authority constituted Under Section 9 of the Act;
- (l) "Section" means the Section of the Act;
- (m) "Taluk Legal Services Committee" means a Taluk Legal Services Committee constituted Under Section 11-A of the Act;
- (n) "Taluk" means a Sub-Division in a District or Tehsil;
- (o) "Lok Adalat" means Lok Adalat constituted Under Section 19 of the Act.
- (p) "Permanent Lok Adalat" means Lok Adalat constituted Under Section 22B of the Act.
- (q) All other words and expressions used in these rules but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Number, experience and qualifications of members of the State Authority.-

- (1) The State Authority shall, including its Patron-in-Chief and the Executive Chairman, have not more than seventeen Members.
- (2) The following shall be ex-officio members of the State Authority, namely:-
 - (i) Advocate General of Uttarakhand;
 - (ii) Principal Secretary in the Department of Finance;
 - (iii) Principal Secretary in the Department of Law;
 - (iv) Principal Secretary in the Department of Revenue;
 - (v) Chairman of the Bar Council of Uttarakhand State;
 - (vi) Chairman, Scheduled Tribes & Scheduled Castes Commission, Uttarakhand;
 - (vii) Director General of Police of the State;
 - (viii) Secretary in the Social Welfare Department;
 - (ix) Two Chairmen of the District Authority, as may be nominated by the State Government, in consultation with the Chief Justice of the High Court.
- (3) The State Government may nominate, in consultation with the Chief Justice of the High Court, five other members from amongst those possessing the experience and qualifications prescribed in sub-rule (4) of this rule.
- (4) A person shall not be qualified for nomination as a member of the State Authority, unless he is-
 - (a) an eminent social worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the Society, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Women, Children, Rural and Urban Labour; or;
 - (b) an eminent person in the field of law or education; or
 - (c) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes.

4. Powers and functions of the Member-Secretary of the State Authority.-

The powers and functions of the Member-Secretary of the State Authority, inter-alia, shall be-

- (a) to give free legal services to the eligible person under Act including weaker sections of the Society.
- (b) to work out modalities of the Legal Services Schemes and programmes approved by the State Authority and ensure their effective monitoring and implementation;
- (c) to exercise the powers in respect of administrative House keeping, Finance and budget matters as Head of the Department in the State Government.

For the purposes of meeting incidental and contingent expenditure, a permanent advance of Rs.25,000/- shall be placed at the disposal of Member-Secretary of the State Authority. All expenditures necessary to carry out the various functions of the State Authority including expenses incurred in holding its meeting shall be made with the prior approval of the Member-Secretary, provided for an expense of more than Rs.10,000/- approval of the Executive Chairman shall be necessary.

- (d) to manage the properties, records and funds of the State Authority;
- (e) to maintain true and proper accounts of the State Authority including checking and auditing in respect thereof periodically;
- (f) to prepare Annual Income and Expenditure Account and Balance-Sheet of the State Authority;
- (g) to liaise with the Social Action Groups and District and Taluk Legal Services Authorities;

- (h) to maintain, up-to-date and complete statistical information including progress made in the implementation of various Legal Services Programmes from time to time;
- (i) to process proposals for financial assistance and issue Utilization Certificates thereof;
- (j) to organize various Legal Services Programmes as approved by the State Authority and convene Meetings/Seminars and workshops connected with Legal Services programmes and preparation of reports and follow-up action thereon;
- (k) to produce video/documentary films, publicity material, literature and publications including Nukkad Natak Plays to inform general public about the various aspects of the Legal Services Programmes;
- (l) to lay stress on the resolution of Rural Disputes and to take extra measures to draw schemes for effective and meaningful legal services for settling Rural Disputes at the door steps of the rural people;
- (m) to perform such of the functions as are assigned to him under the schemes formulated under Clause (b) of Section 4 of the Act; and
- (n) to coordinate the functioning of the High Court Legal Services Committee and to exercise effective control over the functioning of the District Authority and the Tehsil Legal Services Authority and to provide them guidance; and necessary assistance in carrying out the programmes and schemes framed under the Act.
- (o) to perform such other functions as may be expedient for efficient functioning of the State Authority.
- (p) to exercise such power and perform such functions and duties as may be assigned to him by the Executive Chairman and;
- (q) to perform such other functions as may be assigned by Central Authority from time to time.
- (r) the Member Secretary is also empowered to call for the judicial record of those pending cases which are required to be referred to Lok Adalat constituted Under Section 19 & 20 of the Act. He is also empowered to serve the notice on opposite party and call for the other record regarding any matter within the jurisdiction of Lok Adalat Under Para (ii) of sub-section 5 of Section 19 in case any application is made before the State Authority by any party at a pre-litigation stage for reconciliation and disposal of his/her/ their case by Lok Adalat, so as to complete the ground work, including obtaining the version of each party for referring the matter to Lok Adalat.

5.1 Appointment, Service Conditions, Powers & Functions of the Executive Chairman.-

5.1 Appointment and Service conditions of Executive Chairman.

A Sitting Judge of the Uttarakhand High Court or a retired Judge of any High Court as recommended by the Chief Justice shall be appointed as the Executive Chairman by the State Government. However, the tenure of such a retired Judge shall not exceed five years; his other service conditions shall be such as may be determined by the Government from time to time in consultation with the Chief Justice, but in all events he shall be entitled to pay and perks as were admissible to him as a Sitting Judge.

- 5.2 (a) The Executive Chairman shall be competent to take all decisions as may be required to carry out the objects of the Act on behalf of the State Authority.
- (b) He shall also be competent to take all decisions as may be required for providing legal aid, legal advice or other legal services to any person directly or indirectly in respect of any matter pending before any court in the State of Uttarakhand including all matters at pre-litigation stage as well.
- (c) He shall be competent to review the cases where legal services have been denied by District/ Tehsil Authority.
- (d) He shall be competent to assess the work done by each of the Chairmen/Secretaries and other Judicial officers of the District/Tehsil Authorities towards the fulfilment of the aspirations

of the people under the Act and shall record suitable entries in this respect and communicate the same to the Hon'ble High Court for placing them in their A.C.Rs. and honorarium of such amount as is fixed by him in consultation with the Chief Justice can also be paid to them as motivation.

6. Terms of office and other conditions of appointment of Members and Membern Secretary of the State Authority.-

- (1) The term of office of the members of the State Authority nominated under sub-rule (3) of rule 3 by the State Government shall be two years and shall be eligible for re-nomination.
- (2) A member of the State Authority, nominated under sub-rule (3) of rule 3 may be removed by the State Government, in consultation with the Chief Justice, if-
 - (a) he fails, without sufficient cause, to attend three consecutive meetings of the State Authority or five meetings held within the space of two years; or
 - (b) has been adjudged as insolvent; or
 - (c) has been convicted of an offence, which in the opinion of the State Authority involves moral turpitudes; or
 - (d) has become physically or mentally incapable of acting as a member; or
 - (e) has so abused his position as to render his continuance in the State Authority prejudicial to the public interest.
 - (f) if in the opinion of the State Authority, it is not desirable to continue him as member.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), no members shall be removed from the State Authority on the ground specified in clause (d) of that sub-rule unless the Chief Justice, on a reference being made to him in this behalf by the State Government or the State Authority, has, on an enquiry held by him in accordance with such procedure as he may specify in this behalf, recommended that the member ought, on such grounds, to be removed.
- (4) A member may, by writing under his hand, addressed to the Chairman, resign from the State Authority and such resignation shall take effect from the date on which it is accepted by the State Government in consultation with the Chief Justice, or on the expiry of 30 days from the date of tendering resignation, whichever is earlier.
- (5) If any member nominated under sub-rule(3) of rule 3 ceases to be member of the State Authority for any reason, the vacancy shall be filled up in the same manner as the original nomination and the person so nominated shall continue to be a member for the residue of the term of his predecessor.
- (6) All members shall be entitled to payment of Travelling Allowances & Daily Allowances in respect of the journeys performed in connection with the work of the State Authority by the Authority. However, in case of a member being a Govt. employee, he shall draw such T.A. /D.A. from the department in which he is employed at the rates to which he is entitled to under the service rules applicable to him.

MEMBER-SECRETARY

- (7) The Member-Secretary of the State Authority shall be a serving member of Uttarakhand Higher Judicial Service in the selection Pay Scale of the cadre will be the whole time employee and shall hold office for a term not exceeding five years, which may be extended for a further period not exceeding one year by the Government in consultation with the Chief Justice.
- (8) In all matters like age of retirement, pay and allowances, benefits and entitlements and disciplinary matters and other conditions of service, the Member-Secretary shall be governed by the rules, as are applicable to the members of the State Higher Judicial Services and shall be on deputation to the State Authority. Deputation Allowance shall however be admissible to him.

7. Officers and other employees of the State Authority.-

- (1) The number of officers and other employees including Officer on Special Duty of the State Authority shall be such as may be determined by the Government, from time to time, in consultation with the Chief Justice.
- (2) The number of officers and other employees including Secretary, Officer-on- Special Duty of the State Authority shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given in Appendix A.
- (3) The State Authority shall have the power to make the appointments of the officers and other employees of the Authority, for the efficient performance of its functions under the Act, subject to the creation of such posts by the State Government. The appointments shall be made as per the rules and regulations applicable for such appointment in the State Government. However, the officers and other employees can also be taken on deputation either from High Court/ Subordinate Courts or from any other departments of the State Govt., as the case may be, in consultation with the State Authority. In case the officers or employees are taken on deputation, such employees shall be entitled to deputation allowance, as per rules.

8. Conditions of service, pay and allowances of the Officers and other employees of the State Authority.

- (1) The Officers and other employees of, the State Authority other than Member Secretary and Officer-on-Special Duty shall be entitled to such pay and allowances as may be determined by the Government, from time to time, in consultation with the Chief Justice.
- (2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are as given in the Appendix A.
- (3) The officers and other employees of the State Authority shall be entitled to such other facilities, allowances and benefits as may be determined by the Government, from time to time, in consultation with the Chief Justice.
- (4) Officer on Special Duty shall be appointed, in consultation with the Chief Justice, from amongst persons belonging to the Uttarakhand Nyayik Sewa not below the Rank of Civil Judge (Senior Division).
- (5) In all matters, like age of retirement, pay and allowances, benefits and entitlements, disciplinary matters and other conditions of service of Officer-on-Special Duty shall be governed by the rules applicable to the service to which they belong. The Officer-on-Special Duty shall be on deputation to the State Authority. He shall be entitled to the deputation allowance.
- (6) Until the terms and conditions of service of officers and other employees of the State Authority other than the Officer-on-Special Duty are prescribed, their qualifications, procedure for recruitment and other conditions of service including disciplinary matters, leave, provident fund and other matters, shall be the same as that of the officers and employees of similar category in the Government and rules relating thereto shall mutatis mutandis apply.

HIGH COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE

9. High Court Legal Services Committee.

9.1 Power & function of the High Court Legal Services Committee

Subject to the general superintendence and control of the State Authority, the High Court Committee shall exercise the following functions namely;

- (a) It shall be the duty of the Committee to give effect to such policies, programmes and schemes of Legal Aid, Legal Advice and Legal Services as may be formulated and required by the Central and the State Authority;
- (b) It shall provide Legal Aid, Legal Advice and Legal Services to persons who are eligible for the

- purpose under the Act or the Rules for High Court cases;
- It shall organize and conduct Lok Adalats for High Court cases;
 - It shall encourage settlement of cases by way of negotiations, arbitration and conciliation;
 - It shall perform such functions as may be delegated to it from time to time by the State Authority.

9.2 Chairman of the High Court Legal Services Committee:

A Sitting Judge of the High Court nominated by the Hon'ble Chief Justice shall be the Chairman of the High Court Legal Services Committee.

9.3 Experience, qualification and honorarium of the Secretary to the High Court Legal Services Committee.

A person shall not be qualified for appointment as Secretary to the High Court Legal Services Committee unless he is an officer of the High Court not below the Rank of Joint Registrar, belonging to the Uttarakhand Higher Judicial Service and shall be paid honorarium of Rs.1,000/- per month or such amount as may be fixed by the Chairman of the Committee in consultation with the Chief Justice.

9.4 Power & Function of Secretary of the High Court Legal Services Committee.

The Secretary of the Committee shall be the Principal Officer of the Committee and shall;

- Be the custodian of all the assets, accounts, record and funds of the Committee and shall work under the supervision and direction of the Chairman;
- Maintain or cause to be maintained true and proper accounts of receipts and disbursements of funds of the Committee in such form and in such manner, as may be specified by the State Authority;
- Exercise such powers and perform such functions and discharge such duties, as may be assigned to him by the Chairman; and
- Perform all other acts as may be expedient and necessary for efficient and proper performance of functions and discharge duties of the Committee.

10. Number of officers and other employees of the High Court Legal Services Committee and their conditions of service, pay and allowances.

- The number of officers and other employees of the High Court Legal Service Committee shall be such as may be determined by the Government, from time to time, in consultation with the Chief Justice.
- The number of officers and other employees of the High Court Legal Services Committee shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in Appendix B.
- All the officers and other employees other than the Secretary, working immediately before the commencement of these rules, in the High Court Legal Aid and Advice Committee shall, on such commencement be the officers and employees of the High Court Legal Services Committee.
- The officers and other employees of the High Court Legal Services Committee shall be entitled to such pay and allowances as may be determined by the Government, from time to time in consultation with the Chief Justice.
- The scales of pay at the time of commencement of these rules are as given in the Appendix B.
- Until the terms and conditions of service of officers and other employees of the High Court Legal Services Committee are prescribed, their qualifications, procedure for recruitment and other conditions of service including disciplinary matters, leave, provident fund and other matters shall be the same as that of the officers and employees of similar category in the Government and rules relating thereto shall Mutatis Mutandis apply.
- The officers and other employees of the High Court Legal Services Committee shall be entitled

to such other facilities, allowances and benefits as may be determined by the Government, from time to time, in consultation with the Chief Justice.

11. Number, duration, experience and qualifications of Chairman & other members of District Authority.

- (1) District Judge, shall be ex-officio Chairman of the District Legal Services Authority. For exceptional services rendered by any District Judge/Chairman of the District Legal Service Authority in this field, he may be paid such amount as honorarium as is fixed by the Executive Chairman in consultation with the Chief Justice and an appropriate entry may also be made in his Annual Confidential Report for the excellent/outstanding work done by him.
- (2) In addition to members nominated under sub-rule (3), a District Authority shall consist of the following ex-officio members-
 - (a) District Magistrate;
 - (b) Senior Superintendent of Police or Superintendent of Police, as the case may be;
 - (c) Chief Judicial Magistrate;
 - (d) District Government Counsel (Civil);
 - (e) District Government Counsel (Criminal);
 - (f) District Government Counsel (Revenue);
 - (g) President of the Bar Association.
- (3) The Government may, in consultation with the Chief Justice, nominate six other members of a District Authority from amongst the persons possessing the experience and qualifications specified in sub-rule (4). The term of such members shall be two years and they shall also be eligible for re-nomination.
- (4) A person shall not be qualified to be nominated as member of a District Authority, unless he is-
 - (a) an eminent social worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the society, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Women, Children, rural and urban labour;
 - (b) an eminent person in the field of law; or
 - (c) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes.

12. Number of Officers and other employees of District Authority-

- (1) Civil Judge (Sr. Div.) or in his absence Chief Judicial Magistrate, as the case may be, shall be ex-officio Secretary of the District Legal Services Authority and shall be paid honorarium of Rs.500/- per month or such amount as may be fixed by the State Authority in consultation with the Chief Justice.
- (2) The number of officers and other employees of a District Authority shall be such as may be determined by the Government, from time to time, in consultation with the Chief Justice.
- (3) All the officers and other employees working, immediately before the commencement of these rules, in a District Legal Aid and Advice Committee shall, on such commencement, be the officers and employees of the District Authority.

13. Conditions of service, pay and allowances of the officers and other employees of District Authority-

- (1) The officers and other employees of the District Authority shall be entitled to such pay and allowances, as may be determined by the Government, from time to time, in consultation with the Chief Justice.
- (2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are as given in Appendix C.
- (3) The officers and other employees of the District Authority shall be entitled to such other facilities,

allowances and benefits, as may be determined by the Government, from time to time, in consultation with the Chief Justice.

- (4) Until terms and conditions of service of officers and other employees of the District Authority are prescribed, their qualifications, procedure for recruitment and other conditions of service including disciplinary matters, leave, Provident Fund and other matters shall be the same as that of the officers and employees of a similar category in the Government and rules relating thereto shall mutatis mutandis apply.

14. Number, duration, experience and qualifications of other members of Taluk/Tehsil Legal Services Committee-

- (1) A Taluk/Tehsil Legal Services Committee shall have not more than five members.
- (2) In addition to members nominated under sub-rule (3) a Taluk/Tehsil Legal Services Committee shall consist of the following ex-officio members.
 - (a) The senior most Judicial Officer of any rank, if posted at Tehsil or in Sub-Division, shall act as Chairman and such Junior most officer shall act as a Secretary of the Taluk/Tehsil Legal Services Committee. In case, only one Judicial officer is posted, Tehsildar shall act as a Secretary and the Secretary shall be paid honorarium @ Rs. 300/- per month or such amount as may be fixed by the State Government in consultation with Chief Justice.
 - (b) In absence of a Judicial Officer, the Sub Divisional Officer, if posted in Taluk/Tehsil shall act as president and Tehsildar shall act as a Secretary.
 - (c) The senior most Gazetted Police Officer posted within the local limits of the Tehsil.
- (3) The Government may in consultation with the Chief Justice, nominate two or three other members of a Taluk/Tehsil Legal Services Committee from amongst the persons possessing the qualifications and experience specified in sub-rule (4). The term of such members shall be two years and they shall also be eligible for re-nomination.
- (4) A person shall not be qualified to be nominated as member of a Taluk/Tehsil Legal Services Committee, unless he is-
 - (a) an eminent social worker who permanently resides within the local limits of the Tehsil concerned and is engaged in the upliftment of the weaker sections of the society, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Women, Children, rural and urban labour.
 - (b) an eminent person in the field of law; or
 - (c) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes.

15. Number of officers and other employees of Taluk/Tehsil Legal Services Committee -

- (1) The number of officers and other employees of a Taluk/Tehsil Legal Services Committee shall be such as may be determined by the Government, from time to time, in consultation with the Chief Justice.
- (2) The officers and other employees of a Taluk/Tehsil Legal Services Committee shall be entitled to such pay and allowances as may be determined by the Government from time to time, in consultation with the Chief Justice.
- (3) The officers and other employees of a Taluk/Tehsil Legal Services Committee shall be entitled to such other facilities, allowances and benefits as may be determined by the Government from time to time, in consultation with the Chief Justice.
- (4) Until terms and conditions of service of officers and other employees of Tehsil Legal Services Committee are prescribed, their qualifications, procedure for recruitment and other conditions of service including disciplinary matters, leave, Provident Fund and other matters shall be the same as that of the officers and employees of similar category in the Government and rules relating thereto shall mutatis mutandis apply.

16. Entitlement to Free Legal Services-

- (1) Every person who is to file or has filed or to defend a case shall be entitled to free legal services from State Legal Services Authority, High Court Legal Services Committee, District Legal Services Authority or Taluk Legal Services Committee as the case may be, under this Act, if that person is-
- (a) a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe;
 - (b) a victim of trafficking in human beings or beggar as referred to in Article 23 of the Constitution;
 - (c) a woman or a child;
 - (d) a mentally ill or otherwise disable person;
 - (e) a person under circumstances of undeserved want such as being a victim of a mass disaster, ethnic violence, caste atrocity, flood, drought, earthquake or industrial disaster; or
 - (f) an industrial workman; or
 - (g) in custody, including custody in a protective home within the meaning of clause (g) of section 2 of the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956, or in a juvenile home within the meaning of clause (i) of section 2 of the Juvenile Justice Act, 1986 in psychiatric hospital or psychiatric nursing home within the meaning of clause (g) of section 2 of the Mental Health Act, 1987; or
 - (h) in receipt of annual income from all sources less than rupees fifty thousand or such other higher amount as may be prescribed by the State Government, if the case is before a court other than the Supreme Court.
 - (i) Ex-service man;

17. LOK ADALATS, CONCILIATION CENTRES & LEGAL LITERACY CAMPS.

17.1 Experience and qualifications for other persons under sub-section (4) of section 19-

A person shall not be qualified to be included in the Bench of Lok Adalat, unless he is-

- (a) an eminent social worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the society, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, women, children and urban labour; or
- (b) a lawyer of standing; or
- (c) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes and Programmes.

17.2 Lok Adalat, Literacy Camps & Conciliation Centres in High Court

The Chairman of the High Court Legal Services Committee, in consultation with the Chief Justice, shall constitute benches of Lok Adalats as and when necessary. Each bench shall comprise of any two or three of the following, namely:-

- (i) A serving or retired Judge of the High Court or any other retired Judicial Officer not below the rank of District Judge;
- (ii) Member Secretary/ Secretary of the High Court Legal Services Committee;
- (iv) A member of the legal profession having not less than 10 years of practice;
- (v) A local social worker of repute who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the society.

17.3 Chairman of the High Court Legal Services Committee in consultation with the Chief Justice shall also constitute a conciliation centre in High Court to provide legal services to the person who satisfies the criteria laid down under the Act and also to scrutinize cases for referring them to the Lok Adalats for decision. The conciliation centre shall be headed by the Secretary of the Committee with any two of the following, namely:-

- (i) A member of the legal profession having not less than 10 years of practice.
- (ii) A local social worker of repute who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the society.

- 17.4 The Chairman of the High Court Legal Services Committee in consultation with the Chief Justice can also hold and organize Legal Literacy Camps at such places in the State as are deemed fit and necessary to achieve the objects of the Act.
- 17.5 The expenditure incurred for organizing a Lok Adalat shall not exceed Rs.10000/- or such other amount as may be fixed from time to time by the State Authority in consultation with the Chief Justice. The expenditure incurred for organizing a Literacy Camp shall not exceed Rs.15000/- or such other amount as may be fixed from time to time by the State Authority in consultation with the Chief Justice.

17.6 Lok Adalat, Conciliation Centre & Literacy Camps by District Authority.

Apart from traditional Lok Adalats, the Chairman of the District Authority shall hold at least one Lok Adalat and one Legal Literacy Camp in his District at District Headquarter or in any of the Tehsil in a month. Such Lok Adalats can however be held on any Saturday or Sunday of the month as per the number of cases referred to such Lok Adalat. Once a case is referred to such Lok Adalat, it can be adjourned to the next Lok Adalat till an amicable solution is reached or till such time, it is felt that no amicable solution is possible and case will have to be sent back to the concerned court for decision in accordance with law. The Presiding Officer of such Lok Adalat may be paid such amount as honorarium as is fixed by the State Authority in consultation with the Chief Justice. The officers can however be motivated by other incentive such as suitable entries in their Annual Confidential Reports for the excellent work in the field of Lok Adalat and Literacy Camps. More benches of Lok Adalats as per the need in their respective Districts/Tehsil can however be constituted by the District Authority depending upon the number of such cases referred to such Lok Adalats. Each bench shall comprise of one or two of the following, namely:-

- (i) A Judicial Officer serving in the District Headquarter or at Tehsil.
- (ii) A member of the legal profession having at least 7 years of practice.
- (iii) A (local) social worker of repute who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the Society.

Note: If suitable members from persons mentioned in sub-clause 'b' or 'c' above are not readily available, the Judicial Officer alone can constitute the Lok Adalat.

- 17.7 The limit of the expenditure to be incurred in organizing a Lok Adalat or a Literacy Camp in District Headquarter or at Tehsil Headquarter shall be the same as prescribed under rule 17.5.
- 17.8 The Executive Chairman of the State Authority shall constitute conciliation Centre/Centres in each District Headquarter and at Tehsil Headquarter for active legal advice and assistance to all persons entitled for it under the Act to resolve the dispute and also to scrutinize cases for referring to Lok Adalat. Such conciliation centre at District Headquarter shall be headed by the Chairman of the District Authority and at Tehsil Headquarter by the Chairman of the Tehsil Committee with one or two of the following members, namely:-

- (i) A member of the legal profession having not less than 10 years of practice.
- (ii) A local social worker of repute who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the society.

In case more than one centre in the District/ Tehsil has been created, it can be manned by any person of the legal profession having not less than ten years of practice.

17.9 State Level Conciliation Centres-

The Executive Chairman in his discretion shall constitute one or more conciliation centre at State level for active legal help and assistance to all those who are entitled for such services under the Act to resolve the dispute amicably so as to achieve the objectives of the Act fully. Such Centres at State level shall be headed by Member Secretary of the State Legal Services Authority or by any other person nominated by the Executive Chairman, if more than one such centres are constituted.

In each such centre one or two of the following members may also be nominated by the Executive Chairman for assistance namely:-

- (i) A member of the legal profession having not less than 10 years of practice.
- (ii) A local social worker of repute who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the Society.

In case more than one such centre have been created, a member of the legal profession having not less than ten years of practice can be deputed to such centre.

17.10 Payment of the honorarium to the person deputed at conciliation centre/centres.

Subject to the availability of funds from Central Authority or from State Govt., the Executive Chairman in consultation with the Central or State Authority, as the case may be, shall be free to fix such amount of honorarium as is deemed fit and necessary for payment to persons nominated to work in such conciliation centre constituted at High Court Level, State Level or at District/ Tehsil Level, as the case may be.

17.11 Payment of Fees to the Panel Lawyers

The State Authority in consultation with the Chief Justice shall fix the quantum of fees to be paid to the Panel lawyers for extending legal advice, aid and assistance to the poor as per the decision of the State or District Authority. Such payment schedule adopted by the State Authority for the time being in force is given in Appendix 'D'. Such payment can however be enhanced by the State Authority in consultation with the Chief Justice as is deemed fit and necessary.

PERMANENT LOK ADALAT

18. Appointment and conditions of Service, Pay and Allowances of Chairman of Permanent Lok Adalat

- (a) a person who is or has been a District Judge or Additional District Judge or has held judicial office equivalent to that of a District Judge, shall be the Chairman of Permanent Lok Adalat.
- (b) He shall be appointed by the State Government on the recommendation of State Authority for a term not exceeding 5 years or till he attains the age of 67 years whichever is earlier.
- (c) When a serving judicial officer is appointed as Chairman, he shall be entitled to the salary and allowances and all other perquisites as were admissible to him as a Serving Officer, but when a retired Judicial Officer is appointed as Chairman, he shall be entitled to the salary and allowances and all other perquisites last drawn by him as a serving judicial officer minus the amount of pension fixed on retirement of such Judicial Officer.

19. Appointment and Sitting Fees and other allowances of other persons of Permanent Lok Adalat.

- (a) Two other members having adequate experience in public Utility Service shall be appointed by the State Government on recommendation of the State Authority.
- (b) Such members shall hold office for a term not exceeding 3 years, which may be extended for a further period of 2 years by the Government in consultation with the State Authority.
- (c) Such members shall be entitled to a Sitting Fee of Rs. 500/- per sitting.
- (d) The Chairman and other persons shall be entitled to such travelling and daily allowances on official tour as admissible to Group 'A' officer of State Government.
- (e) For the purpose of attending the sitting of Permanent Lok Adalat, such other person shall be entitled to conveyance allowance of Rs.2500/- per month.

- (f) Before appointment, the Chairman and other person shall have to give an undertaking that he does not and will not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function as Chairman or other person.
- (g) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions, the Chairman or other persons may:-
 - (a) by writing under his hand and addressed to the State Authority or, as the case may be, the District Authority, resign his office at any time;
 - (b) be removed from his office in accordance with the provisions of rule 20.
- (h) When the Chairman is unable to discharge his functions owing to absence, illness or, any other cause, the senior-most (in order of appointment) person of Permanent Lok Adalat holding office for the time being shall discharge the functions of the Chairman until the day on which the Chairman resumes the Charge of his functions.
- (i) The Chairman or any Other Person ceasing to hold office as such shall not hold any appointment in, or be connected with, the management or, administration of an Organization which has been the subject of the proceeding under the Act during his tenure for a period of five years from the date on which he ceases to hold such office.

20. Resignation and removal-

The State Authority or District Authority, as the case may be, may remove from office, Chairman or any other member of Permanent Lok Adalat, who:-

- (a) has been adjudged an insolvent; or
- (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Authority, involves moral turpitude; or
- (c) has become physically or mentally incapable of acting as such Chairman or Other Person; or
- (d) has acquired such financial or other interest as it likely to affect prejudicially his functions as Chairman or member; or
- (e) has or so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest;

Provided that the Chairman or any other member shall not be removed from his office on the grounds specified in clauses (d) and (e), except on inquiry held in accordance with the procedure prescribed in rule 21.

21. Procedure for inquiry-

- (1) When the State Authority or, as the case may be, District Authority is of the opinion that an allegation; under clause (d) or Clause (e) of rule 5 is required to be inquired into, it may hold an inquiry against the accused person and shall draw or cause to be drawn up the substance of the allegation which shall contain a statement of relevant facts and a list of documents and witnesses.
- (2) The State Authority or, as the case may be, District Authority shall deliver or, cause to be delivered to accused person a copy of the allegation and a list of documents and witnesses and shall require him to submit within such time as may be allowed, a written reply or statement of his defence.
- (3) If the allegations are admitted by the accused person, the State Authority or, as the case may be, District Authority shall record reasons and remove the accused person.
- (4) Where the charges have been denied by the accused person, the State Authority or, as the case may be, District Authority may appoint an Officer to inquire into the truth of the allegations and it may also appoint a Presenting Officer to present the case on behalf of the State Authority or, as the case may be, District Authority before the Inquiry Officer.
- (5) The Enquiry Officer shall give an opportunity to the Presenting Officer to present the case within such time as may be allowed by him from time to time. After the evidence is closed by

the Presenting Officer, the accused person, shall be given an opportunity to present his defence in respect of allegations within such time as may be allowed by the Enquiry Officer.

- (6) The Enquiry Officer shall have power to call witnesses and record their statements or receive evidence on affidavits or call for production of documents or other relevant records, which may be necessary for the enquiry.
- (7) The Enquiry Officer shall submit his report within a period of six months or within such time as may be extended by the State Authority or, as the case may be, District Authority.
- (8) If the State Authority or, as the case may be, District Authority is satisfied that the charges are proved on the basis of the report submitted by the Enquiry Officer, it shall remove the delinquent Chairman or the member, as the case may be.

22. Place of Settings-

- (1) The Permanent Lok Adalat may sit at a place specified by the State Authority or the District Authority, as the case may be.
- (2) The working days and office hours of the Permanent Lok Adalat shall be the same as that of the State Government, as the case may be.
- (3) The sitting of the Permanent Lok Adalat, as and when necessary, shall be convened by the Chairman.

23. Staff of Permanent Lok Adalat-

The State Government, as the case may be, shall provide such staff as may be necessary to assist the Permanent Lok Adalat in its day-to-day work and perform such other functions as is provided under the Act and these rules, which are assigned to it by the Chairman. The salary payable to such staff shall be defrayed out of the Consolidated Fund of State, as the case may be.

24. Saving and Repealing Clause:-

- (1) With the coming into force, the Uttaranchal State Legal Services Authority Rules 2006, the Uttar Pradesh State Legal Services Authority Rules 1996, shall stand repealed in their application to the State of Uttarakhand.
- (2) However, all acts done and action taken under Uttar Pradesh State Legal Services Authority Rules 1996, before coming into force these Rules, shall stand protected.

APPENDIX 'A'

[See Rules 7 (2) and 8 (2)]

S. No.	Name of post	Number of post	Scales of pay
1.	Secretary	1	Selection scales of pay admissible to the members of the Uttaranchal Higher Judicial service.
2.	Officer-on-Special Duty	1	Civil Judge (Sr. Div.) rank.
3.	Personal Secretary	1	Rs.6500-10200
4.	Personal Assistant	2	Rs.5500-9000
5.	Stenographer	2	Rs.4000-6000
6.	Administrative Officer	1	Rs.5500-9000
7.	Upper Division Assistant	2	Rs. 4500-7000
8.	Accounts Clerk	1	Rs. 4000-6000
9.	Typist	2	Rs.3050-4590
10.	Junior Clerk	2	Rs.3050-4590
11.	Library Clerk	1	Rs.3050-4590
12.	Orderly/Peon	6	Rs.2550-3200
13.	Daftary/Machine Operator	1	Rs.2610-3550
14.	Driver	3	Rs.3050-4590
15.	Sweeper-cum-Farrash	1	Rs. 2000.00 per month fixed pay

APPENDIX 'B'

[See Rules 10(2) and 10(5)]

S. No.	Name of post	Number of post	Scales of pay
1.	Clerk	2	Rs.3050-4590
2.	Orderly/Peon	2	Rs.2550-3200

APPENDIX 'C'

[See Rules 12(2) and 13(2)]

S. No.	Name of post	Number of post	Scales of pay
1.	Clerk	13	Rs.3050-4590
2.	Peon	13	Rs.2550-3200

APPENDIX-D
[See Rule 17(11)]

For Service Tribunal

- | | | |
|---|---|---|
| 1. For Conducting the proceedings Before the Tribunal | — | For first 3 days Rs. 150, thereafter Rs. 100 for each day but subject to maximum of Rs. 1500. |
| 2. For giving legal advice | — | Rs. 250 per case |
| 3. Drafting & Pleading which includes rejoinder as well as affidavit. | — | Rs. 500 including advice |

For Labour Courts

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. For the drafting, pleading including legal advice for a case. | — | Rs. 250 |
|--|---|---------|

For Magistrate Court

Bail Application

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1. Bailable Cases | — | Rs. 100 per application |
| 2. Non Bailable Cases | — | Rs. 300 per application |
| 3. Miscellaneous application | — | Rs. 250 per application |
| 4. Appeal/Revision (Panchayat) | — | Rs. 300 per appeal/revision |
| 5. Legal Advice in Civil Cases | — | Rs. 250 per case |
| 6. Legal Advice in Criminal Cases | — | Rs. 250 per case |

In Revenue Cases including consolidation matters

1. High Court	—	Rs. 2500
2. Revenue Board	—	Rs. 1500 per case
3. Commissioner/Add.Com./ DDC/Joint Director	—	Rs. 1000 per case
4. Assistant Collector/S.O.C./ Additional Collector	—	Rs. 750 per case
5. Tehsildar/A.C.O./C.O.	—	Rs. 500 per case
6. Legal Advice in Revenue matters	—	Rs. 300 per case

Session Cases

1. Conducting before the Sessions Courts	—	For 3 days Rs. 200 per day subject to maximum Rs. 2000 for the whole case.
2. Criminal Appeal from 1st Class Magistrate	—	Rs. 1000 per appeal
3. Criminal Appeal against Magistrate 2nd Class's order	—	Rs. 500 per appeal
4. Criminal Revision	—	Rs. 1000 per revision
5. Bail Application	—	Rs. 500

Judicial Magistrate/Chief Judicial Magistrate/Civil Judge/Senior Civil Judge

1. Original Civil Suit	—	Rs. 1000 per case
2. Trial or Warrant Cases	—	Rs. 1000 per case
3. Summon Cases	—	Rs. 500 per case
4. Committal to session Cases including remand proceedings	—	Rs. 250 per case

District and Session Judge/Additional District and Session Judge/Family Court

1. Opinion in Civil Cases	—	Rs. 300 per case
2. Opinion in Criminal Cases	—	Rs. 300 per case
3. Drafting of Civil Pleadings	—	Rs. 500 per case
4. Drafting of Criminal Complaint	—	Rs. 500 per case
5. Matrimonial/Rent Cases	—	Rs. 1500 per case
6. Civil Appeal	—	Rs. 1500 per appeal
7. Case decided Ex-party or Case withdrawn or Case leading to compromise	—	Rs. 500 per case
8. Civil Revision	—	Rs. 750 per revision
9. Criminal Appeal	—	Rs. 750 per appeal
10. Application for insolvency or succession certificate	—	Rs. 750 per application

Motor Accident Claim Cases

1. In Case of Injuries	—	Rs. 1000 per case
2. In Case of Death	—	Rs. 1000 per case

High Court

1. Writ Petition	—	Maximum Rs. 4000 per Case excluding other incidental expenditure after disposal of cases at High Court Level.
2. Habeas Corpus Petition	—	Rs. 2500 per petition
3. 1st Appeal Civil	—	Rs. 3000 per appeal
4. Civil Revision	—	Rs. 750 per revision
5. Criminal Appeal	—	Rs. 2000 per appeal
6. Criminal Revision	—	Rs. 750 per revision
7. Bail Application	—	Rs. 1500

8. Written Legal Opinion in Civil Suits	—	Rs. 750 per opinion
9. Preparation of affidavit & Miscellaneous	—	Rs. 750 per draft

Miscellaneous

1. Execution Cases	—	Rs. 1000 per case
2. Jail Meeting	—	Rs. 250/-

By order of
Smt. Indira Ashish,
Secretary,
Law cum Legal Remembrancer,
Government of Uttarakhand